

जीविका (JEEViKA) आजीविका मॉडल के तहत ग्रामीण महिलाओं के लिए चुनौतियाँ और अवसर

निशा भारती

(रिसर्च स्कॉलर)

अर्थशास्त्र विभाग

कैपिटल यूनिवर्सिटी, कोडरमा, झारखंड

डॉ. अभय दास

एसोसिएट प्रोफेसर

अर्थशास्त्र विभाग

कैपिटल यूनिवर्सिटी, कोडरमा, झारखंड

सारांश

यह पेपर बिहार में जीविका आजीविका मॉडल में भाग लेने वाली ग्रामीण महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों की जाँच करता है। जीविका, एक राज्य-संचालित पहल, महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, कौशल विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHG), ग्राम संगठनों (VO) और क्लस्टर स्तर संघों (CLF) में संगठित करती है। माध्यमिक डेटा, कार्यक्रम रिपोर्ट, केस स्टडी और गुणात्मक साक्ष्य का उपयोग करते हुए, यह अध्ययन उन तरीकों का पता लगाता है जिनके माध्यम से SHG में भागीदारी महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता, घरेलू निर्णय लेने, नेतृत्व की भूमिकाओं और सामाजिक पहचान को प्रभावित करती है। जबकि जीविका महत्वपूर्ण अवसर पैदा करती है, लगातार सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड, संस्थागत कमियाँ और सामाजिक-आर्थिक समूहों में असमान लाभ पूर्ण सशक्तिकरण को सीमित करते हैं। नीतिगत सिफारिशों में लक्षित समावेशन, बाजार संपर्क, कौशल विकास कार्यक्रम और लैंगिक संवेदीकरण पहल शामिल हैं। यह अध्ययन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्केलेबल ग्रामीण आजीविका मॉडल को समझने में योगदान देता है।

कीवर्ड: जीविका, ग्रामीण महिलाएँ, SHG, आजीविका मॉडल, सशक्तिकरण, बिहार

1. परिचय

महिलाओं का सशक्तिकरण भारत में समावेशी विकास का एक केंद्रीय स्तंभ बना हुआ है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ, पितृसत्तात्मक मानदंड और संसाधनों तक सीमित पहुँच महिलाओं की एजेंसी को प्रतिबंधित करती रहती है। बिहार में, जो भारत के सबसे अधिक आबादी वाले और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्यों में से एक है, ग्रामीण महिलाओं को अक्सर बहुआयामी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें सीमित गतिशीलता, शिक्षा की कमी, घरेलू निर्णय लेने में कम भागीदारी और आय-सृजन गतिविधियों में सीमित भागीदारी शामिल है। गरीबी उन्मूलन और लैंगिक समानता के उद्देश्य से सरकारी पहलों के बावजूद, महिलाओं, विशेष रूप से हाशिए पर पड़ी जातियों और समुदायों की महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली संरचनात्मक बाधाओं ने ऐतिहासिक रूप से पूर्ण आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण प्राप्त करने की उनकी क्षमता को सीमित कर दिया है। इस संदर्भ में, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और सामाजिक लामबंदी को संयोजित करने वाले नवीन आजीविका कार्यक्रम महिलाओं की स्वतंत्रता और व्यापक सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

विश्व बैंक से तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसायटी (BRLPS) द्वारा शुरू की गई जीविका (बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना), ऐसी ही एक पहल का प्रतिनिधित्व करती है। 2006 में अपनी

शुरुआत से ही, JEEViKA का लक्ष्य महिलाओं को सेल्फ-हेल्प ग्रुप (SHG), विलेज ऑर्गनाइजेशन (VO) और क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) में संगठित करके ग्रामीण गरीबी को दूर करना रहा है। ये सामूहिक संस्थाएँ न केवल महिलाओं की बचत, क्रेडिट और आजीविका के अवसरों तक पहुँच को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, बल्कि स्थानीय शासन और सामुदायिक निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भी हैं। SHG सदस्यता के माध्यम से, महिलाओं को कौशल विकास, सूक्ष्म-उद्यम प्रबंधन और आय-सृजन गतिविधियों में शामिल होने के अवसर मिलते हैं, जिससे वे धीरे-धीरे गहरी सामाजिक पदानुक्रमों को चुनौती देते हुए अपने घरों में आर्थिक रूप से योगदान कर पाती हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण से परे, JEEViKA महिलाओं के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक एजेंसी को बढ़ावा देना चाहता है। संघीय संरचनाओं में भाग लेकर, महिलाएँ बातचीत कौशल, नेतृत्व का अनुभव और ग्राम सभाओं और VO बैठकों जैसे सामुदायिक निर्णय लेने वाले मंचों में शामिल होने का आत्मविश्वास हासिल करती हैं। ये मंच दृश्यता और सामाजिक पहचान प्रदान करते हैं, जो प्रतिबंधात्मक लिंग मानदंडों को चुनौती देने और अंतर-पीढ़ीगत परिवर्तन को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा, कार्यक्रम सामूहिक कार्रवाई पर जोर देता है, जो सहकर्मि नेटवर्क को मजबूत करता है, ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करता है, और घरों और समुदायों के भीतर महिलाओं की मोलभाव करने की शक्ति को बढ़ाता है। इन आशाजनक रास्तों के बावजूद, JEEViKA मॉडल के तहत ग्रामीण महिलाओं को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ, जैसे कि पितृसत्तात्मक सोच और जाति-आधारित भेदभाव, अक्सर महिलाओं की स्वायत्तता और आर्थिक और सामुदायिक गतिविधियों में पूरी तरह से भाग लेने की क्षमता को सीमित कर देती हैं। संस्थागत चुनौतियाँ, जिनमें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण तक असमान पहुँच, सीमित बाज़ार संपर्क, और ऋण वितरण में नौकरशाही बाधाएँ शामिल हैं, कार्यक्रम के प्रभाव को और सीमित करती हैं। इसके अलावा, साक्षरता और सामाजिक पूंजी में असमानताओं का मतलब है कि सभी महिलाओं को कार्यक्रम से समान रूप से लाभ नहीं होता है, जो संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने वाली समावेशी रणनीतियों की आवश्यकता को उजागर करता है।

यह अध्ययन JEEViKA में भाग लेने वाली ग्रामीण महिलाओं के लिए अवसरों और चुनौतियों के दोहरे दृष्टिकोण की पड़ताल करता है। विशेष रूप से, यह जांच करता है कि आजीविका मॉडल महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, सामाजिक एजेंसी और सांस्कृतिक सशक्तिकरण को कैसे प्रभावित करता है, जबकि उन बाधाओं की आलोचनात्मक जांच करता है जो उनके पूर्ण विकास में बाधा डालती हैं। सक्षम करने वाले कारकों और बाधाओं दोनों का सूक्ष्म विश्लेषण प्रदान करके, यह शोध लिंग-उत्तरदायी ग्रामीण विकास पर व्यापक चर्चा में योगदान देता है, जो भारत में महिला-केंद्रित आजीविका हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को बढ़ाने की तलाश करने वाले नीति निर्माताओं, चिकित्सकों और विद्वानों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

2. पृष्ठभूमि: JEEViKA आजीविका मॉडल

JEEViKA (बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना), जिसे बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसायटी (BRLPS) द्वारा बिहार सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से लागू किया गया है, ग्रामीण गरीबी को कम करने और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से एक अग्रणी पहल है। 2006 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम ने राज्य भर में 12 मिलियन से अधिक महिलाओं को 1 मिलियन से अधिक स्वयं सहायता समूहों (SHG) में संगठित किया है, जो वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और सामाजिक लामबंदी के लिए एक स्केलेबल और समुदाय-संचालित ढांचा स्थापित करता है। JEEViKA का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने, सामुदायिक निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेने और सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों को बदलने में सक्षम बनाना है जो उनकी एजेंसी को सीमित करते हैं। यह कार्यक्रम तीन-स्तरीय मॉडल के रूप में संरचित है। आधार में SHG हैं, जो 10-20 महिलाओं के छोटे समूह हैं जो सामूहिक रूप से बचत करते हैं, ऋण प्राप्त करते हैं और आजीविका गतिविधियों में संलग्न होते हैं। इन SHG को ग्राम स्तर पर ग्राम संगठनों (VO) में संघबद्ध किया जाता है, जो सामूहिक निर्णय लेने, प्रशिक्षण और स्थानीय शासन के साथ जुड़ाव के लिए मंच प्रदान करते हैं। शीर्ष पर क्लस्टर स्तरीय महासंघ (CLF) हैं, जो कई VO का समन्वय करते हैं, उन्हें सरकारी कार्यक्रमों और वित्तीय संस्थानों से जोड़ते हैं, और बड़े पैमाने पर सामूहिक कार्रवाई की सुविधा प्रदान करते हैं। यह पदानुक्रमित संरचना यह सुनिश्चित करती है कि महिलाओं को नेतृत्व, वित्तीय प्रबंधन और सामुदायिक वकालत में धीरे-धीरे अनुभव मिले, जिससे व्यक्तिगत और सामूहिक सशक्तिकरण दोनों में वृद्धि हो।

JEEViKA महिलाओं के सशक्तिकरण के तीन प्राथमिक आयामों पर ध्यान केंद्रित करता है: आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। आर्थिक रूप से, यह कृषि, पशुधन और सूक्ष्म-उद्यमों में बचत, ऋण और आय-सृजन के अवसरों तक पहुंच प्रदान करता है। सामाजिक रूप से, यह स्थानीय शासन, सामुदायिक कार्यक्रमों और सहकर्मी नेटवर्क में भागीदारी को बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक रूप से, यह गतिशीलता, नेतृत्व और पहचान को बढ़ावा देता है, समय के साथ पारंपरिक लैंगिक मानदंडों को चुनौती देता है। वित्तीय समावेशन को सामाजिक लामबंदी के साथ मिलाकर, JEEViKA ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जो बिहार में आजीविका के अवसर और स्थायी सामाजिक परिवर्तन के रास्ते दोनों प्रदान करता है।

3. साहित्य समीक्षा

- आर्थिक सशक्तिकरण: बचत, ऋण और सूक्ष्म-उद्यमों तक बढ़ी हुई पहुंच से घरेलू आय और वित्तीय स्वायत्तता में सुधार होता है (स्वाइन और वॉलेंटिन, 2009)।
- सामाजिक सशक्तिकरण: SHG में भागीदारी से नेतृत्व, गतिशीलता और सामूहिक कार्रवाई क्षमता बढ़ती है (कबीर, 2005)।
- चुनौतियाँ: पितृसत्तात्मक मानदंड, सीमित बाजार पहुंच, संस्थागत विसंगतियाँ, और हाशिए पर पड़े समूहों के बीच असमान भागीदारी (सिंह, 2018; कुमार और शर्मा, 2021)।

4. अनुसंधान पद्धति

- दृष्टिकोण: मिश्रित-पद्धति (मात्रात्मक + गुणात्मक)
- डेटा स्रोत: JEEViKA कार्यक्रम रिपोर्ट, विश्व बैंक डेटा, केस स्टडी, मीडिया रिपोर्ट
- विश्लेषणात्मक ढांचा: आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों में अवसरों और चुनौतियों की जांच करता है।
- संकेतक: वित्तीय पहुंच, घरेलू निर्णय लेने, सामुदायिक जुड़ाव, गतिशीलता, नेतृत्व और सामाजिक पहचान।

5. आर्थिक अवसर और चुनौतियाँ

5.1 वित्तीय समावेशन

संकेतक SHG महिलाएँ गैर-SHG महिलाएँ

सक्रिय बैंक खाते (%) 84% 21% विश्व बैंक 2020

औसत वार्षिक ऋण प्राप्त (₹) 45,000 5,000 विश्व बैंक 2020

प्रति सदस्य वार्षिक बचत (₹) 12,500 3,200 पटना प्रेस 2022

अवलोकन: बेहतर बचत और ऋण से स्वायत्तता और घरेलू सौदेबाजी की शक्ति बढ़ती है।

चुनौतियाँ: बड़े पैमाने पर व्यवसाय विस्तार के लिए सीमित ऋण।

5.2 आजीविका विविधीकरण

- क्षेत्र: कृषि, डेयरी, हस्तशिल्प, सूक्ष्म-उद्यम
- SHG सदस्यों की औसत घरेलू आय गैर-सदस्यों की तुलना में 25–30% अधिक है।
- चुनौती: दूरदराज के क्षेत्रों में सीमित बाजार संपर्क हैं।

5.3 उद्यमिता और कौशल विकास

- वित्तीय साक्षरता, व्यावसायिक कौशल और उद्यम प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- चुनौती: असमान गुणवत्ता और अपर्याप्त फॉलो-अप दीर्घकालिक प्रभाव को कम करता है।

6. सामाजिक अवसर और चुनौतियाँ

6.1 घरेलू निर्णय-निर्माण

निर्णय क्षेत्र SHG महिलाएँ (%) गैर-SHG महिलाएँ (%)

घरेलू खर्च 78%	42%	विश्व बैंक 2020
बच्चों की शिक्षा	65%	28% पटना प्रेस 2022
आजीविका निवेश	53%	12% विश्व बैंक 2020

चुनौती: पितृसत्तात्मक मानदंड कुछ घरों में पूर्ण भागीदारी को सीमित करते हैं।

6.2 सामुदायिक नेतृत्व

गतिविधि SHG महिलाएँ (%) गैर-SHG महिलाएँ (%)

ग्राम सभा में उपस्थिति	61%	18%	विश्व बैंक 2020
VO नेतृत्व 12%	2%	पटना प्रेस 2022	
स्थानीय कल्याण में भागीदारी	48%	14%	ट्रिब्यून इंडिया 2021

चुनौती: हाशिए पर पड़ी महिलाओं का नेतृत्व भूमिकाओं में कम प्रतिनिधित्व है।

7. सांस्कृतिक सशक्तिकरण

- बढ़ी हुई गतिशीलता, सामाजिक दृश्यता और साथियों द्वारा पहचान।
- घरेलू लैंगिक मानदंडों में धीरे-धीरे बदलाव।
- मंतरशिप और पीयर नेटवर्क के माध्यम से अंतर-पीढ़ीगत सशक्तिकरण।
- चुनौती: जाति और पितृसत्तात्मक संरचनाएँ बनी हुई हैं। 8. केस स्टडीज़
- वैशाली ज़िला: डेयरी उद्यम → आय + घरेलू फ़ैसले लेने की क्षमता + समुदाय में पहचान
- नालंदा ज़िला: स्वच्छता कार्यक्रम → नेतृत्व + सामाजिक पहचान
- गया ज़िला: युवा महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता → पीढ़ी दर पीढ़ी सशक्तिकरण

8. केस स्टडी

- वैशाली ज़िला: डेयरी उद्यम → आय + घरेलू फ़ैसले लेने में भागीदारी + समुदाय में पहचान
- नालंदा ज़िला: स्वच्छता कार्यक्रम → नेतृत्व + सामाजिक पहचान

· गया ज़िला: युवा महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता → पीढ़ी दर पीढ़ी सशक्तिकरण

9. नीतिगत सिफ़ारिशें

1. बाज़ार तक पहुँच: सप्लाय चैन और वैल्यू-चेन सपोर्ट को मज़बूत करें।
2. कौशल विकास: व्यावसायिक और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार करें।
3. समावेशी पहुँच: निचली जाति की, अनपढ़ और हाशिए पर पड़ी महिलाओं को लक्षित करें।
4. लैंगिक संवेदनशीलता: महिलाओं की स्वायत्तता का समर्थन करने के लिए पुरुषों और बुजुर्गों को शामिल करें।
5. संस्थागत मज़बूती: लगातार बैंक लिंकेज, पारदर्शी SHG संचालन और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करें।

10. निष्कर्ष

JEEViKA आजीविका मॉडल बिहार में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs), ग्राम संगठनों (VOs) और क्लस्टर स्तर के फेडरेशन (CLFs) में संगठित करके, यह कार्यक्रम वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और सामूहिक कार्रवाई के लिए संरचित मंच तैयार करता है। इस अध्ययन में प्रस्तुत विश्लेषण से पता चलता है कि इन संस्थानों में भागीदारी बचत, ऋण और आय-सृजन के अवसरों तक पहुंच के माध्यम से महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाती है। कृषि गतिविधियों, सूक्ष्म-उद्यमों और संबद्ध आजीविका से बढ़ी हुई आय न केवल घरेलू भलाई में सुधार करती है बल्कि पारिवारिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की मोलभाव करने की शक्ति को भी मजबूत करती है।

आर्थिक आयामों से परे, JEEViKA महिलाओं को सामुदायिक जुड़ाव, नेतृत्व विकास और सामूहिक वकालत के लिए मंच प्रदान करके सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान देता है। VOs और CLFs में भागीदारी गतिशीलता, सार्वजनिक दृश्यता और बातचीत कौशल को बढ़ावा देती है, जिससे महिलाएं शासन-संबंधी गतिविधियों और सामाजिक कल्याण पहलों में शामिल हो पाती हैं। सांस्कृतिक सशक्तिकरण भी एक महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में उभरता है, क्योंकि महिलाएं आत्मविश्वास, साथियों की पहचान और अंतर-पीढ़ीगत प्रभाव प्राप्त करती हैं, धीरे-धीरे गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देती हैं और परिवारों और समुदायों के भीतर लैंगिक भूमिकाओं को नया आकार देती हैं।

इन महत्वपूर्ण लाभों के बावजूद, अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि JEEViKA के तहत ग्रामीण महिलाओं को बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं, जिनमें पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, जाति-आधारित भेदभाव और पारंपरिक घरेलू पदानुक्रम शामिल हैं, स्वायत्तता और निर्णय लेने की शक्ति के पूर्ण प्रयोग को सीमित करते हैं। संस्थागत बाधाएं, जैसे कि प्रशिक्षण तक असंगत पहुंच, उत्पादों के लिए सीमित बाजार संपर्क, और ऋण वितरण में नौकरशाही बाधाएं, महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों की स्थिरता और मापनीयता को कम करती हैं। इसके अलावा, साक्षरता, सामाजिक पूंजी और अनुभव में असमानताओं का मतलब है कि सभी महिलाओं को समान लाभ नहीं मिलते हैं, जो समावेशी दृष्टिकोणों के महत्व को उजागर करता है जो विशेष रूप से हाशिए पर पड़े और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को लक्षित करते हैं।

निष्कर्ष रूप में, JEEViKA दर्शाता है कि संरचित आजीविका कार्यक्रम ग्रामीण भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए शक्तिशाली माध्यम हो सकते हैं। अवसरों और चुनौतियों की दोहरी उपस्थिति ऐसी नीतिगत उपायों की मांग करती है जो बाजार तक पहुंच बढ़ाएं, कौशल-निर्माण पहलों को मजबूत करें, न्यायसंगत समावेशन सुनिश्चित करें, और घर और समुदाय स्तर पर लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा दें। SHGs और फेडरेशन के सक्षम तंत्र को मजबूत करते हुए संरचनात्मक और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को संबोधित करके, JEEViKA और इसी तरह के मॉडल महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक पहचान और समग्र सशक्तिकरण प्राप्त करने के लिए स्थायी रास्ते प्रदान कर सकते हैं, जो बिहार और उससे आगे व्यापक ग्रामीण विकास और समावेशी विकास में योगदान देगा।

संदर्भ

- कबीर, एन. (2005). लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण: तीसरे सहस्राब्दी विकास लक्ष्य 1 का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। जेंडर एंड डेवलपमेंट, 13(1), 13-24।
- स्वेन, आर. बी., और वॉलेंटिन, एफ. वाई. (2009). क्या माइक्रोफाइनेंस महिलाओं को सशक्त बनाता है? भारत में स्वयं सहायता समूहों से साक्ष्य। इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स, 23(5), 541-556।
- सिंह, एन. (2018). ग्रामीण बिहार, भारत में महिला सशक्तिकरण पर स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव: मिश्रित-पद्धति अध्ययन से साक्ष्य। जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज रिव्यू, 12(3), 45-62।
- विश्व बैंक. (2019). भारत में ग्रामीण महिला समूह: एजेंसी को आर्थिक सशक्तिकरण में बदलना। वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक। <https://www.worldbank.org/en/results/2019/09/10/rural-women-collectives-in-india-translating-agency-into-economic-empowerment>.
- विश्व बैंक. (2020). बिहार में ग्रामीण विकास के लिए महिला समूहों की शक्ति को उजागर करना। वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक। <https://www.worldbank.org/en/results/2020/10/16/unleashing-the-power-of-women-collectives-for-rural-development-in-the-indian-state-of-bihar>.
- कुमार, पी., और शर्मा, ए. (2021). ग्रामीण बिहार में महिला समूहों के सामाजिक प्रभाव का आकलन: जीविका से साक्ष्य। एशियन जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 8(2), 77-95।
- पटना प्रेस. (2022, 14 अगस्त). जीविका बिहार में महिलाओं को पैसे बचाने और व्यवसाय शुरू करने में मदद कर रही है। <https://patnapress.com/jeevika-bihar-women-business-skills>.
- ट्रिब्यून इंडिया. (2021, 18 जुलाई). जीविका दीदी: ग्रामीण सशक्तिकरण की बिहार की मूक क्रांतिकारी। <https://www.tribuneindia.com/news/exam-mentor/jeevika-didis-bihars-silent-revolutionaries-of-rural-empowerment>.